

प्रत्येक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

लगातार,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग— 5

देहरादून, दिनांक, 3) दिसम्बर, 2012

विषय: जिला चिकित्सालय हरिद्वार के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल के पुनरीक्षण
प्रावकालन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-124/XXVIII-5/2006-23/2006, दिनांक 06.03.2006 तथा आपके पत्र सं०-7प/1/आवासीय भवन/20/2005/38214, दिनांक 08.11.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला चिकित्सालय हरिद्वार के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल के निर्माणाधीन कार्यों हेतु मूल लागत ₹55.10 लाख के सापेक्ष गठित पुनरीक्षित आगणन ₹71.10 लाख के विरुद्ध टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹66.14 लाख (रूपये छासठ लाख चौदह हजार मात्र) पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्व में अवमुक्त ₹55.10 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012-13 में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि ₹11.04 लाख (रूपये ग्यारह लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, हरिद्वार को उपलब्ध करायी जायेगी। अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वर्ष में करते हुए सम्पूर्ण अवशेष कार्यों को स्वीकृत पुनरीक्षण लागत में ही पूर्ण करते हुए भवन विभाग को इसी वित्तीय वर्ष में हस्तगत कर दिया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं। अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 4- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाये।
- 5- कार्य करने एवं सामग्री कय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का कड़ाई से पालन किया जाय।
- 6- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

- 7- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- 8- कार्य बनाने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ जरूर कर ले। निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।
- 9- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं०-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19.06.2012 एवं शासनादेश सं०-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में इंगित निर्देशों एवं उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
- 10- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शा० सं०-2047/xiv-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- 11- कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम०ओ०यू० करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्यय 2012-13 के अनुदान सं०-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था-00 आयोजनागत, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०-169(P)/XXVII(3)/1012-13 दिनांक 26.12.2012 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:-सॉफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

(अतर सिंह)

उप सचिव

संख्या- 1535(1)XXVIII-5-2012-23/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 4- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 6- मुख्य चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 8- परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, हरिद्वार।
- 9- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-3/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा

(अतर सिंह)

उप सचिव